

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 760 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2022 — पौष 10, शक 1944

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग  
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर —492001

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

दिशा—निर्देश

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु समूह निवल मीटरिंग एवं प्रतीयमान निवल मीटरिंग) दिशा—निर्देश 2022**

क्र. 96/सी.एस.ई.आर.सी./2022.— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 के विनियम 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं इस बाबत सक्षमता प्रदान करने वाली अन्य समस्त शक्तियों को वापरते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, समूह निवल मीटरिंग एवं प्रतीयमान निवल मीटरिंग पद्धति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अंतर्गत, निम्नलिखित दिशा—निर्देशों की रचना करता है।

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

- 1.1 इन दिशा—निर्देशों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु समूह निवल मीटरिंग एवं प्रतीयमान निवल मीटरिंग) दिशा—निर्देश, 2022 कहा जा सकता है।
- 1.2 यह दिशा—निर्देश छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

**2. परिभाषाएं**

- 2.1 इन दिशा—निर्देशों में जब तक संदर्भ अन्यथा आशयित ना हो

अ) “समूह निवल मीटरिंग” से अभिप्रेत है — एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के द्वारा आवेशित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली अथवा बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली द्वारा उत्पादित/अंतर्प्रवाहित ऊर्जा आधिक्य को निवल मीटर के माफत ग्रिड को निर्यात किया जाता है तथा निर्यातित ऊर्जा का समायोजन उसी एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में स्थित उसी एक उपभोक्ता के एकाधिक विद्युत सेवा संयोजनों में किया जाता है।

- ब) “प्रतीयमान निवल मीटरिंग” से अभिप्रेत है – एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के द्वारा आवेशित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली अथवा बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली द्वारा उत्पादित/अंतर्प्रवाहित ऊर्जा आधिक्य को निवल मीटर के मार्फत ग्रिड को निर्यात किया जाता है तथा निर्यातित ऊर्जा का समायोजन उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में स्थित प्रतिभागी उपभोक्ताओं के एकाधिक विद्युत सेवा संयोजनों में किया जाता है।
- स) “पात्रताधारी उपभोक्ता” से अभिप्रेत है – वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में स्थित ऐसा विद्युत उपभोक्ता जो अपनी स्वयं की विद्युत आवश्यकता की अंशतः अथवा पूर्णतः भरपाई करने के लिये अपनी स्वयं की अथवा अन्य पक्षकार की सौर्य ऊर्जा परियोजना का उपयोग करता है।
- 2.2 इस दिशा-निर्देश में इस्तेमाल किये गये ऐसे अन्य सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें विशिष्टतः परिभाषित नहीं किये गये हैं, का अभिप्राय वही होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 में अभिप्रेत है।
3. सामान्य एवं प्रयुक्तता
- (1) समूह निवल मीटरिंग पद्धति, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त उपभोक्ताओं पर लागू होगा।
  - (2) प्रतीयमान निवल मीटरिंग पद्धति, आवासीय उपभोक्ताओं, सामुहिक गृह-निर्माण समितियों तथा शासकीय/स्थानीय प्राधिकरणों हेतु लागू होगा।
  - (3) समूह निवल मीटरिंग अथवा प्रतीयमान निवल मीटरिंग पद्धति के तहत किसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता 1 किलोवाट से कम अथवा 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
  - (4) किसी पात्रताधारी उपभोक्ता के परिसर में स्थापित की जाने वाली क्षमता, पात्रताधारी उपभोक्ता के स्वीकृत भार अथवा अनुबंधित मांग से अधिक नहीं होगी।
  - (5) उपभोक्ता स्वयं की खपत हेतु नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे तथा उन्हें आधिक्य ऊर्जा को ग्रिड में खपाने की अनुमति होगी, जिसे निवल मीटरिंग के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत समायोजित किया जाएगा।
  - (6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011, समय-समय पर यथा-संशोधित, के प्रावधानों तथा उसके तहत जारी आदेशों के अनुसार नेटवर्क सुदृढ़ करेगा।
  - (7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 की कंडिका 22.1(डी) तथा उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप सविस्तार तकनीकी अध्ययन करेगा।
4. वितरण ट्रांसफार्मर के स्तर पर उपलब्ध क्षमता
- वितरण नेटवर्क से अंतर्संयोजित रहने की अनुमति दी गयी वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की सकलीकृत क्षमता, संबंधित वितरण ट्रांसफार्मर की 100% क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- परंतु यह कि अधिक क्षमता की स्थापना की स्थिति में, विद्युत प्रदाय संहिता, विद्युत ग्रिड संहिता और आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जाएगी ताकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना की अनुमति की मनाही से बचाव हो सके।
5. आवेदन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया
- आवेदन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 की कंडिका 15 के अनुरूप होगी।

## 6. अंतर्संयोजकता, प्रतिमान एवं सुरक्षा

ग्रिड के साथ अंतर्संयोजकता : तकनीकी प्रतिमान एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 के प्रावधानों एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता, 2011 तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप होंगे।

## 7. मीटरिंग व्यवस्था

- (1) निवल मीटरिंग व्यवस्था, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 की कंडिका 11 के अनुरूप होगी।
- (2) निवल मीटर की लागत, जो विद्युत के आयात एवं निर्यात दोनों को दर्ज करने में सक्षम हो, का अभिप्राय होगा वर्तमान उपभोक्ता मीटर की लागत, यदि हटा दिया जाए तथा ऐसे नये स्थापित निवल मीटर की लागत का अंतर उपभोक्ता के द्वारा वहन की जाएगी।

## 8. समूह निवल मीटरिंग पद्धति के तहत बिलिंग एवं ऊर्जा लेखांकन की प्रक्रिया

- (1) समूह निवल मीटरिंग के तहत, विद्युत संयोजन(नों) की बिलिंग एवं ऊर्जा लेखांकन की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप होगी।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 में दिये गये प्रावधानों एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अतिरिक्त, आगे यह प्रावधानित किया जाता है कि –
  - अ. जहाँ किसी देयक अवधि में इकाईओं का निर्यात इकाईओं के आयात से, संयोजन पर जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थित है, अधिक हो जाता है, ग्रिड में अंतर्प्रवाहित ऐसी अधिक इकाईओं को, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी वरीयता सूची में इंगित क्रमानुसार, सेवा संयोजन(नों) के मासिक देयक में खपत हुई ऊर्जा के मुकाबिल समायोजित किया जाएगा। समायोजन हेतु वरीयता का क्रम, उस स्थान के सेवा संयोजन से प्रारंभ माना जाएगा जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थित है।
  - ब. शेष आधिक्य ऊर्जा के, अन्य विद्युत संयोजन(नों) में से, समायोजन के वास्ते वरीयता सूची को उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।
  - स. किसी समय-खंड (जैसे- शीर्ष-काल, गैर-शीर्ष-काल, सामान्य-काल इत्यादि) में खपत हुई विद्युत प्रथमतः उस स्थान के समकक्ष समय-खंड में उपभोक्ता के तत्सम देयक-चक्र में हुए विद्युत उत्पादन, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थित है, में से भरपाई की जाएगी। तथा कोई अंतर्प्रवाहित आधिक्य इकाईओं को उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी वरीयता सूची में इंगित क्रमानुसार, सेवा संयोजन(नों) के मासिक देयक में खपत हुई ऊर्जा के मुकाबिल समायोजित किया जाएगा मानो कि आधिक्य उत्पादन/ऊर्जा समाकलन, टाईम ऑफ़ डे (टी.ओ.डी.) उपभोक्ताओं के लिये गैर-शीर्ष-काल समय-खंड तथा गैर-टी.ओ.डी. उपभोक्ताओं के लिये सामान्य समय-खंड में उपजा हो।
  - ड. जहाँ किसी देयक-अवधि में विद्युत संयोजन(नों) द्वारा इकाईओं का निर्यात, गैर-टी.ओ.डी. टैरिफ या टी.ओ.डी. टैरिफ में इकाईओं के आयात से अधिक हो जाता है, उपभोक्ता द्वारा अंतर्प्रवाहित ऐसी आधिक्य इकाईओं को आगामी देयक-अवधि में, ऊर्जा समाकलन के रूप में आगे सरकाया जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा निपटान अवधि के दौरान पश्चातवर्ती देयक-अवधिओं में वरीयता सूची में इंगित क्रम में ऊर्जा की खपत के मुकाबिल समायोजनार्थ निर्यातित ऊर्जा के रूप में दर्शाया जाएगा।
  - ई. आधिक्य को आगे सरकाने अथवा ऊर्जा समाकलन का बकाया-भुनाया हिसाबने के मकसद हेतु ऊर्जा इकाईओं को सुसंगत वर्ष हेतु लागू टी.ओ.डी. टैरिफ के सुसंगत छूट/अधिभार के प्रतिशत के अनुसार माध्यर्थ किया जाएगा। देयक-चक्र में किसी समय-खंड में कोई खपत से अधिक उत्पादन को इस तरह से लेखांकित किया जाएगा मानो कि आधिक्य उत्पादन/ऊर्जा समाकलन टी.ओ.डी. उपभोक्ताओं हेतु गैर-शीर्ष समय-खंड में तथा गैर-टी.ओ.डी. उपभोक्ताओं हेतु सामान्य समय-खंड में उपजा हो।

### 9. प्रतीयमान निवल मीटरिंग पद्धति के तहत बिलिंग एवं ऊर्जा लेखांकन की प्रक्रिया

- (1) प्रतीयमान निवल मीटरिंग के तहत, विद्युत संयोजन(नों) की बिलिंग एवं ऊर्जा लेखांकन की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप होगी।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम, 2019 में दिये गये प्रावधानों एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अतिरिक्त, आगे यह प्रावधानित किया जाता है कि –
  - अ. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित ऊर्जा को प्रत्येक प्रतिभागी उपभोक्ता(ओं) के मासिक विद्युत देयक में, उपभोक्ता(ओं) के द्वारा किये गये अनुबंध/समझौता ज्ञापन में इंगित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से क्रय के अनुपात के अनुरूप, समाकलित किया जाएगा।
  - ब. उपभोक्ता(ओं) को वित्तीय वर्ष में एक बार, दो माह की अग्रिम सूचना देकर, उपभोक्ता(ओं) के द्वारा किये गये अनुबंध/समझौता ज्ञापन में इंगित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से क्रय के अनुपात के अध्यधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से विद्युत के समाकलन के अंश को परिवर्तित करने का अवसर उपलब्ध होगा।
  - स. जहाँ किसी प्रतिभागी उपभोक्ता(ओं) का सेवा संयोजन किसी कारणवश, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत असंयोजित हुआ हो, उस उपभोक्ता की असमायोजित इकाईओं/बकाया समाकलन का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा।
  - ड. किसी समय-खंड (जैसे – शीर्ष-काल, गैर-शीर्ष-काल, सामान्य-काल इत्यादि) में खपत हुई विद्युत प्रथमतः समकक्ष समय खंड में प्रतिभागी उपभोक्ता(ओं) के तत्सम देयक-चक्र में हुए विद्युत उत्पादन, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थित है, में से भरपाई की जाएगी। देयक-चक्र में किसी समय-खंड में कोई खपत से अधिक उत्पादन को इस तरह से लेखांकित किया जाएगा मानो कि आधिक्य उत्पादन/ऊर्जा समाकलन गैर-शीर्ष समय-खंड में उपजा हो।
  - ई. जहाँ किसी प्रतिभागी उपभोक्ता की देयक-अवधि में समाकलित इकाईआं उस उपभोक्ता द्वारा आयात की गयी इकाईओं से अधिक हो, ऐसी अधिक समाकलित इकाईओं को आगामी देयक-अवधि में, प्रत्येक प्रतिभागी उपभोक्ता(ओं) की निपटान अवधि के दौरान पश्चातवर्ती देयक-अवधिओं में ऊर्जा की खपत के मुकाबिल समायोजनार्थ ऊर्जा समाकलन के रूप में आगे सरकाया जाएगा।
  - फ. आधिक्य को आगे सरकाने अथवा ऊर्जा समाकलन का बकाया-भुनाया हिसाबने के मकसद हेतु ऊर्जा इकाईओं को सुसंगत वर्ष हेतु लागू टी.ओ.डी. टैरिफ के सुसंगत छूट/अधिभार के प्रतिशत के अनुसार माध्यर्थ किया जाएगा।

### 10. आधिक्य ऊर्जा हेतु वित्तीय वर्ष के अंत में टैरिफ

वित्तीय वर्ष के अंत में आधिक्य ऊर्जा हेतु टैरिफ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर. ई.) विनियम, 2019 की कंडिका 21.7 एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप होगी।

### 11. चोरी एवं मीटर(रों) का विरूपण

विद्युत की चोरी एवं मीटर(रों) का विरूपण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 की कंडिका 11 एवं उसकी पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप होगी।

**12. विवादों का निपटारा**

देयक संबंधित कोई विवाद, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, से अधिशासित होंगे।

**13. अन्य प्रभारों की प्रयुक्तता**

समूह निवल मीटरिंग एवं प्रतीयमान निवल मीटरिंग व्यवस्था के तहत स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, व्हीलिंग, क्रॉस सब्सिडि, पारेषण एवं वितरण तथा बैंकिंग प्रभारों एवं अधिभारों से मुक्त होगी।

**14. नवीकरणीय क्रय प्रतिबद्धता**

उत्पादन मीटर द्वारा दर्ज किया गया वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, नवीकरणीय क्रय प्रतिबद्धता (आर.पी.ओ.) के अनुपालन में जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (डी.आर.ई.) विनियम एवं उसके पश्चातवर्ती संशोधनों में अनुबद्ध किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा लेखांकित किया जाएगा।

**15. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र यंत्रव्य में हिस्सा लेने की पात्रता**

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु मान्यता एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 एवं उसके पश्चातवर्ती संशोधनों में विनिर्दिष्ट पात्रता के क्रतीरों के अनुरूप होगी।

**16. शिथिलीकरण की शक्ति**

आयोग, स्वतः अथवा किसी हितधारी व्यक्ति के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर, इस दिशा-निर्देश के प्रावधानों को, सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश के द्वारा, लिखित में कारण दर्ज करते हुए तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, शिथिल कर सकता है।

**17. संशोधन करने की शक्ति**

आयोग, समय-समय पर इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों में वृद्धि, बदलाव, परिवर्तन, निलंबित, नवरूपित, संशोधन या निरसन कर सकता है।

**टीपः—** इस दिशा-निर्देशों के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./—

(एस.पी. शुक्ला)

सचिव.

Raipur, the 22nd December 2022

## GUIDELINES

**Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Group Net Metering and Virtual Net Metering for Renewable Energy) Guidelines, 2022**

No. 96/CSERC/2022.— In exercise of powers conferred under Regulation 26 of the CSERC (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Guidelines for implementation of Group Net Metering and Virtual Net Metering framework under CSERC (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 and its subsequent amendments.

**1. Short title and commencement**

- 1.1 These Guidelines may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Group Net Metering and Virtual Net Metering for Renewable Energy) Guidelines, 2022.
- 1.2 These Guidelines shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

**2. Definition**

- 2.1 In these Guidelines, unless the context otherwise requires:
  - a) **“Group Net Metering”** means an arrangement whereby surplus energy generated/injected from a Renewable Energy System or Battery Energy Storage System (BESS) charged through Renewable Energy System is exported to the grid through Net Meter and the exported energy is adjusted in more than one electricity service connection(s) of the same consumer located within the same distribution licensee’s area of supply;
  - b) **“Virtual Net Metering”** means an arrangement whereby entire energy generated/injected from a Renewable Energy System or Battery Energy Storage System (BESS) charged through Renewable Energy System is exported to the grid from renewable energy meter/ gross meter and the energy exported is adjusted in more than one electricity service connection(s) of participating consumers located within the same distribution licensee’s area of supply;
  - c) **“Eligible Consumer”** means a consumer of electricity in the area of supply of the distribution licensee, who uses a self-owned or third party owned solar power project, to offset part or all of the consumer’s own electricity requirements.
- 2.2 All other words and expressions used in these guidelines although not specifically defined herein shall have the meaning assigned to them in the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulations, 2019, as amended from time to time. (In short CSERC DRE Regulations, 2019).

**3. General & Applicability**

- (1) Group Net Metering Framework shall be applicable for all consumers of Chhattisgarh State.
- (2) Virtual Net Metering Framework shall be applicable for residential consumers, Group housing societies, and establishments of Government/Local Authorities.
- (3) The capacity of the Renewable Energy System under Group Net Metering or Virtual Net Metering framework to be installed by any Renewable Energy Generator shall not be less than 1 kilo Watt and more than 500 kilo Watt.
- (4) The capacity to be installed at any eligible consumer premises shall not exceed the sanctioned load or contract demand of the eligible consumer.
- (5) Consumer will generate renewable energy for self-consumption and are allowed to feed the excess energy into the grid, which shall be adjusted under Net-metering as per provisions under CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments as per these guidelines.
- (6) The distribution licensee shall carry out network augmentation as per the provisions of Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2011 as amended from time to time and Orders issued there under.
- (7) The Distribution licensee shall carry out detailed technical study as per clause 22.1 (d) & (e) of the CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments.

**4. Available Capacity at Distribution Transformer level**

The cumulative capacity of distributed renewable energy systems allowed to be interconnected with the distribution network shall not exceed 100% of the respective distribution transformer capacity.

Provided that in case of excess installation, distribution transformer capacity shall be increased to avoid denial of permission for setting up Renewable Energy system as provisions of the Supply Code/Grid Code/Orders issued by the Commission

**5. Procedure for Application and Registration**

Procedure for Application and Registration shall be as per clause 15 of the CSERC DRE Regulations, 2019.

**6. Interconnectivity, Standards and Safety**

Interconnection with the grid: technical standards and safety shall be as per provisions in CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments, Chhattisgarh State Electricity Grid Code, 2011 and Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2011 and its subsequent amendments.

**7. Metering Arrangement**

- (1) Net metering arrangement shall be as per clause 11 of the CSERC DRE Regulations, 2019.
- (2) Cost of the Net Meter, which is capable of recording both import and export of electricity, shall mean the differential cost between existing consumer meter, if removed and such a new Net Meter is installed to be borne by the consumer.

**8. Procedure for billing and energy accounting under Group Net Metering Framework:**

- (1) The procedure for billing and Energy accounting of electricity connection(s) under Group Net Metering shall be as per CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments.
- (2) In addition to the provisions in CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments, it is further provided that –
  - a. Where the export of units during any billing period exceeds the import of units at the connection where Renewable Energy system is located, such surplus units injected into the grid shall be adjusted against the energy consumed in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the consumer. The sequence of priority for adjustment shall be deemed to begin with the service connection where the Renewable Energy System is located.
  - b. The priority list for adjustment of the balance surplus energy against other electricity connection(s) may be revised by the consumer once in every financial year with an advance notice of two months.
  - c. The electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, normal hours etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the similar time blocks in the same billing cycle of the consumer where the Renewable Energy System is located and any surplus units injected shall be adjusted against the energy consumed in the monthly bill of service connection(s) in a sequence indicated in the priority list provided by the consumer as if the surplus generation/ Energy Credits occurred during the off peak time block for Time of Day (ToD) consumers and normal time block for Non-ToD consumer.
  - d. Where during any billing period the export of units either in Non-ToD Tariff or ToD Tariff exceeds the import of units by the electricity service connection(s), such surplus units injected by the consumer shall be carried forward to the next billing period as energy credit and shown as energy exported by the consumer for adjustment against the energy consumed in subsequent billing periods within the settlement period in the sequence indicated in the priority list.
  - e. For the purpose of carry forward of surplus or set off of energy credits, the energy units shall be moderated as per the relevant rebate/surcharge percentage of ToD tariff applicable for the relevant year. Any surplus generation over consumption in any time block in a billing cycle shall be accounted as if the surplus generation/ Energy Credits occurred during the off-peak time block for ToD consumers and normal time block for Non ToD consumer.

**9. Procedure for billing and energy accounting under Virtual Net Metering Framework:-**

- (1) The procedure for billing and Energy accounting of electricity connection(s) under Virtual Net

Metering shall be as per CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments.

- (2) In addition to the provisions in CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments, it is further provided that –
- a. The energy generated from Renewable Energy System shall be credited in the monthly electricity bill of each participating consumer(s) as per the ratio of procurement from Renewable Energy System indicated under the agreement/ MoU entered by the consumer(s)
  - b. The consumer(s) shall have the option to change the share of credit of electricity from Renewable Energy System subject to the ratio of procurement from Renewable Energy System indicated under the agreement/ MoU entered by the consumer(s) once in the financial year with an advance notice of two months
  - c. Where the service connection of any participating consumer(s) is disconnected due to any reason under any law for the time being in force, the unadjusted units/ remaining credits of that consumer shall be paid by the distribution licensee at the end of the financial year.
  - d. The electricity consumption in any time block (e.g., peak hours, off-peak hours, normal hours etc.) shall be first compensated with the electricity generation in the similar time blocks in the same billing cycle of the participating consumer(s). Any surplus generation over consumption in any time block in a billing cycle shall be accounted as if the surplus generation/ Energy Credits occurred during the offpeak time block.
  - e. Where the units credited during any billing period of any participating consumer exceeds the import of units by that consumer, such surplus credited units shall be carried forward in the next billing period as energy credits for adjustment against the energy consumed in subsequent billing periods within the settlement period of each participating consumer(s).
  - f. For the purpose of carry forward of surplus or set off of energy credits, the energy units shall be moderated as per the relevant rebate/surcharge percentage of ToD tariff applicable for the relevant year.

**10. Tariff at the end of financial year for surplus energy**

Tariff at the end of financial year for surplus energy shall be as per clause 21.7 of the CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments.

**11. Theft and Tempering of Meter(s)**

Theft of electricity and tampering of meter(s) shall be as per the provisions in clause 11 of the Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2011 and its subsequent amendments.

**12. Dispute Resolution**

Any dispute in billing shall be governed as per the provisions in Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011 as amended from time to time.

**13. Applicability of other charges**

The Renewable Energy system set up under group net metering and virtual net metering arrangement shall be exempted from all wheeling, cross subsidy, transmission and distribution and banking charges and surcharges.

**14. Renewable Purchase Obligation**

The quantum of distributed renewable energy generation as recorded by the generation meter shall be accounted by the distribution licensee towards compliance of its Renewable Purchase Obligation (RPO) as stipulated in CSERC DRE Regulations, 2019 and its subsequent amendments.

**15. Eligibility to participate under Renewable Energy Certificate mechanism**

The issuance of Renewable Energy Certificate shall be as per the eligibility criteria specified under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof.

**16. Power to relax**

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after



giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these Guidelines on its own motion or on an application made before it by an interested person.

**17. Power to amend**

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these guidelines.

By Order of the Commission

Sd/-

**(S.P. Shukla)**  
Secretary.